शिक्षा और भूमंडलीकरण

❑ जे. वलक

अनुवाद : निर्मल मिश्रा

सांस्कृतिक दृष्टि से भूमंडलीकरण मानकीकरण और विविधीकरण की दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को जन्म देता है । आबादी के विभिन्न समूहों की स्वच्छंदता को दूर करते हुए जीवन शैलियों, संचार, भाषाओं, और संस्कृतियों के मानकीकरण की लहर के कारण, अल्पसंख्यकों की पहचानों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में, और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रतिरोध सामने आ रहा है । यह अलग बात है कि अभी यह प्रतिरोध कारगर नहीं हो पा रहा। इसमें शक नहीं कि शिक्षा ही भू-मंडलीकरण से उत्पन्न समस्याओं के उत्तर देगी । सामाजिक पुनरेकीकरण के तत्व के रूप में शिक्षा को एक नया और विविधता से संपन्न रुप ग्रहण करना होगा । पर यह खास तौर पर भविष्य में, वह प्रमुख तत्व बनी रहेगी जो व्यक्तियों को अपने भाग्य के नियंत्रण में समर्थ बनायेगी । प्रस्तुत आलेख कुछ ऐसी निष्पत्तियां सामने रखता है।

शिक्षा के विकास के अध्येता, जोम्तिएन कांफ्रेंस में की गई सिफारिशों से सुपरिचित हैं। वे मानते हैं कि शिक्षा में सुलभता, गुणवत्ता, प्रासंगिकता, समानता, लिंग और दक्षता जैसे मुद्दों को उठाना आवश्यक है । साथ ही यह सुझाव भी दिया जाता है कि नीति-निर्माताओं, योजनाकारों, निर्णयकर्ताओं, शिक्षा शास्त्रियों और प्रबंधकों को अपने शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण बदलने चाहियें । उन्हें राज्य और विदेशी संगठन संबंधी सरोकारों की जगह शिक्षा के सभी समर्थकों के अधिक स्वामित्व, भागीदारी, सहयोग और लामबंदी के पक्ष में; व्यवस्थाओं की जगह संस्थाओं और विद्यालयों के पक्ष में, लागतों की जगह संसाधनों के आवंटन के परिणामों संबंधी मानदंडों के पक्ष में; उच्चतर स्तरों की जगह बुनियादी शिक्षा के पक्ष में; अध्यापक-केन्द्रित शिक्षा के पक्ष में; रट्टामारी पर बेहद जोरे देने वाली परंपरागत व्यवस्थाओं की जगह पठन-पाठन की अधिक सक्रिय और सहभागी रणनीतियों के पक्ष में आम सहमति बनानी चाहिये ।

यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय आयोग के काम का समापन करते हुए डेलर्स रिपोर्ट ने अपने उद्देश्यों की एक बेहद सघन, समृद्ध और व्यापक कार्यसूची प्रस्तुत की है। यह कार्यसूची आने वाले दशकों में शिक्षा व्यवस्थाओं की अनेक विशेषताओं का निर्धारण करेगी। ये हैं - (1) कुछ बनने के लिए शिक्षा (2) कुछ सीखने के लिए शिक्षा, (3) कुछ करने के लिए शिक्षा और, (4) साथ-साथ जीने के लिए शिक्षा ।

जोम्तिएन सम्मेलन में और डेलर्स आयोग के विचार विमर्श के दौरान देखने में भूमंडलीकरण (ग्लोबलाइजेशन) कुछ वर्षों में भागीदारों का एकमात्र और प्रमुख दरकार नहीं थी । फिर भी दोनों में शिक्षा के सुधार और पुर्नरचना (भूमंडलीकरण) के प्रभाव पर भारी ध्यान दिया गया था । इसलिए उनके निष्कर्षों और उनकी सिफारिशों को उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत समझा जाना चाहिए जिनका सरोकार शैक्षिक नीतियों और सुधारों पर भूमंडलीकरण के प्रभावों से है ।

भूमंडलीकरण की प्रमुख विशेषताएं

भूमंडलीकरण आज का एक बहुचर्चित विषय है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह समाज पर भारी प्रभाव डाल रहा है । भूमंडलीकरण वास्तव में वस्तुओं, सेवाओं, और पूंजी के मुक्त आदान प्रदान का समन्वय है । यह प्रवृत्ति इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के साथ शुरू हुई । 19 वीं सदी के उत्तरार्ध में औपनिवेशिक शोषण के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति ने इस प्रवृत्ति को प्रमुखता प्रदान की । 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय प्रक्रिया के निरंतर आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों (1947 में गैट समझौतों) के अनुमोदन ने हमारे समाज में भूमंडलीकरण की गति को बनाये रखा और तेज किया है । फिर भी पिछले कुछ वर्षों में हम इस प्रवृत्ति में भारी तेजी देखते हैं जिसकी तीन बुनियादी विशेषताएं हैं । पहली विशेषता पूरी दुनिया में आर्थिक स्वतंत्रता का विस्तार है और दूसरी विशेषता प्रौद्योगिकी प्रवर्तनों में वृद्धि है , खासकर संचार के क्षेत्र में । तीसरी विशेषता इन विभिन्न आयामों की आपसी निर्भरता हैं । फिर भी सबसे बचकर भूमंडलीकरण के लिए इन सभी तत्वों के परिणामों के कारण ही यह हमारे समाज में इतना प्रभावशाली हो सका है ।

भूमंडलीकरण के तीन आयाम

आर्थिक और वित्तीय आयाम : भूमंडलीकरण सबसे पहले एक आर्थिक संवृत्ति है जो पूरी दुनिया में फैल रही है । इसका भौगोलिक प्रसार हो रहा है । 19 वीं सदी में विश्वव्यापी आर्थिक़ गतिविधि मुख्यत: विकासशील देशों पर तथा अविकसित क्षेत्रों की परिधि पर केंद्रित थी । आज करोड़ों चीनी, रूसी, भारतीय, इतालवी और ग्वाटेमाली एक भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं । यह प्रवृत्ति अभी शुरु हुई है । इसके आरंभ में सिर्फ वस्तुएं, सेवाएं और पूंजी सीमाएं पार करती थीं । पर आज उत्पादन के सभी तत्वों का विनिमय हो रहा है - प्रौद्योगिकी का, उत्पादन के मानकों और साधनों का, श्रम का और खासकर नियंत्रण मुक्ति के बाद वित्त का।

अर्थव्यवस्था के पास आज एक विश्वव्यापी आर्थिक कार्यक्षेत्र है - वस्तुओं और सेवाओं के बाजार, रोजगार बाजार और पूंजी बाजार आदि की दृष्टि से । सभी आर्थिक सिद्धांतों, कंपनियों की रणनीतियों और आर्थिक नीतियों तक को एक विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में एक विकास के सभी पक्षों पर ध्यान देना होगा ।

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आयाम : संचार, जैव-प्रौद्योगिकी और माइक्रो-इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्रों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रवर्तनों का तीव्र प्रसार भूमंडलीकरण की शक्ति को सक्रिय बनाता है । प्रौद्योगिकी प्रवर्तन विनिमय को बढ़ावा देता, उत्पादन में तेजी लाता तथा पूरी दुनिया में विचारों, सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान संभव बनाता है ।

संचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की प्रगति ने भूमंडलीकरण की अत्यंत नाटकीय और गोचर विशेषता को जन्म दिया है । जहां पहले दिन और हफ्ते लगते थे, उलझन भरे बुनियादी ढांचों की जरूरत होती थी और भौतिक कठिनाइयां आती थीं, वहीं अब बिंब और संदेश पल भर में समंदर पार पहुंच जाते हैं । संचार का एक एकीकृत तंत्र आज सभी समाजों के वैचारिक जीवन तथा राजनैतिक और सांस्कृतिक दशाओं को प्रभावित कर रहा है । इस संचारी समाज ने अपने उपभोक्ताओं को सूचना के रूप या परिमाण के बारे में अनेक विकल्प प्रदान किए हैं । उपभोक्ता जब चाहे सूचना प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी सुविधा के अनुसार जिससे चाहे सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं । लेकिन विकल्पों के इस परिमाण के कारण एकरूपता की एक प्रवृति विकसित हो रही है । एकरूपता की इस प्रवृत्ति की व्याख्या इस तथ्य के आधार पर की जा सकती है कि उपभोक्ताओं की संख्या प्रसारमान होने के बावजूद दुनिया की आबादी का बहुत छोटा सा भाग है जो मुख्यत: दुनिया के एक भाग में केन्द्रित है । संचार की भाषा - अंग्रेजी के जरिये एकरूपता के विकास को कुछ लोग इनसान की समझ में सुधार और एक विश्वव्यापी समाज की दिशा में प्रगति मानते हैं । कुछ प्रेक्षकों का विश्वास है कि इससे अभिव्यक्ति की प्रमाणिकता समाप्त नहीं होती, न ही यह विभिन्न भाषाई समूहों के बीच संचार की समान क्षमता संभव बनाती है ।

भूमंडलीकरण के आयामों की आपसी निर्भरता : भूमंडलीकरण की प्रमुख विशेषता उसके विभिन्न आयामों की आपसी निर्भरता है । प्रौद्योगिकी प्रवर्तनों ने पूंजी का प्रवाह इस कदर बढ़ाया है कि उससे उत्पन्न स्टाक बाजार अपनी जगह बदलता हुआ दिन में 24 घंटे काम करता है । पूंजी का परिमाण भी इस कदर बढ़ा है कि आर्थिक क्षेत्र कमजोर पड़ा है और इससे बहुत सारे देश प्रभावित हुए हैं । उत्पादन के सभी तत्वों संबंधी आर्थिक प्रवाहों में वृद्धि से कंपनियों की आपसी निर्भरता बढ़ रही है । इससे जो प्रक्रिया पैदा हो रही है वह एक ऐसे पृथ्वी व्यापी जगत, एक विश्व व्यापी समाज को ही जन्म देगी जो निरंतर सामाजिक संगठन के नए रूप पैदा करता रहे तथा नए ज्ञान-विज्ञान का उत्पादन सुनिश्चित बनाए । इसका आरोपण समाज के सभी ढांचों पर होता है जिनको विश्वव्यापी विकास से तालमेल बनाए रखने के लिए लगातार अपना अनुकूलन करते रहना होगा ।

सामाजिक संगठन के लिए भूमंडलीकरण के परिणाम: भूमंडलीकरण की ये विशेषताएं मानव समाजों के संगठन पर गहरा प्रभाव डालती है । फलस्वरूप हमें अपने समाजों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकने के लिए उन पर पुनर्विचार करना होगा ।

भू-राजनैतिक परिणाम : दुनिया में आरपार हो रहे प्रभावों की वृद्धि वह चीज पैदा करती है जिसे हम सीमाओं की अस्थिरता कह सकते हैं । सीमाएं आमतौर पर उन क्षेत्रों की पहचान के लिए खींची जाती है जिनमें एक राष्ट्र राज्य की स्थापना होती है। जब सीमाओं का क्षरण होता है, राष्ट्र-राज्य के अधिकारी अपनी कार्रवाई की क्षमता में ह्रास पाते हैं । औद्योगिक, मौद्रिक और वित्तीय नीति की दृष्टि से हम सभी सरकार की जोड़तोड़ की क्षमता में धीरे-धीरे कमी आते देख रहे हैं । फलस्वरूप हर राष्ट्रीय और सामाजिक नीति विश्व की आर्थिक़ स्थिति, विश्वव्यापी प्रवृत्तियों, और बाजार की आवश्यकताओं पर बुरी तरह निर्भर दिखाई देती है ।

सांस्कृतिक आयाम : सांस्कृतिक दृष्टि से भूमंडलीकरण मानकीकरण और विविधीकरण की दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को जन्म देता है । खानपान की आदतों, पहनावे और सांस्कृतिक उत्पादों का मानकीकरण समाजों के जीवन की दशाओं में समानताएं बढ़ा रहा है । दूसरी ओर विविधीकरण विश्व की धरोहर को विविध विशेषताओं की सुलभता बढ़ाकर समाजों के बहुरंगी पखों को

सुरक्षित रखने के प्रयास करता है। इसके अलावा आबादी के विभिन्न समूहों की स्वच्छंदता को दूर करते हुए जीवन शैलियों, संचार, भाषाओं और संस्कृतियों के मानकीकरण की लहर के कारण, अल्पसंख्यकों की पहचानों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में, और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रतिरोध सामने आ रहा है । पर यह प्रतिरोध हमेशा कारगर भी नहीं होता। भूमंडलीकरण को अवलंब मिलता है प्रभुत्वशाली माडलों से और जन-संचार के तंत्रों से, जिनका प्रतिरोध करना कठिन होता है।

देशों और समाजों का विखंडन : हमने जिन प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया है वे विश्वव्यापी हैं, अर्थात् पूरी धरती उनसे प्रभावित हो रही है और होगी । पर इसका मतलब यह नहीं कि सभी देशों की प्रतिक्रिया एक जैसी होगी । भूमंडलीकरण की विशेषता तीन प्रकार के कर्ताओं का उदय है : (1) जो भूमंडलीकरण करते हैं, (2) जिनका भूमंडलीकरण होता है, और (3) जो भूमंडलीकरण में पीछे रह जाते हैं। भूमंडलीकरण करने वालों का ध्यान पूंजी, संसाधनों; ज्ञान और सूचना के नियंत्रण पर केन्द्रित होता है । जिनका भूमंडलीकरण होता है वे सूचना में कमजोर और ज्ञान में कमजोर श्रमिक और उपभोक्ता हैं । जो इसमें पीछे छूट जाते हैं उनकी सूचना और ज्ञान तक कोई पहुंच नहीं है या बहुत कम पहुंच है । उपभोक्ता के रूप में उनमें ग्रहण की क्षमता नहीं हैं और उत्पादन के लिए उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। दोनों समाजों और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह विखंडन और विभाजन अब अधिकाधिक तीखा बनता जा रहा है । हर देश में इन तीनों प्रकार के व्यक्ति और समूह मौजूद हैं । भूमंडलीकरण करने वाले अल्पमत में हैं और संभवत: रहेंगे, पर समाज अपनी सामाजिक एकजुटता की शक्ति और अपनी संस्थाओं के एकीकरण की समीक्षा के अनुसार भूमंडलीकरण से प्रभावित अवश्य होगा ।

भूमंडलीकरण और शिक्षा : कुछ सावधानियां

शैक्षिक सुधारों और परिवर्तनों पर भूमंडलीकरण के प्रभावों पर अमल करते हुए हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अल्प अवधि में कुछ अपवादों को छोड़ दें तो कक्षा, विद्यालय या शिक्षा प्रक्रिया में जो हो रहा है उस पर भूमंडलीकरण का अनुभूत प्रभाव संभवत: कम ही होगा।

इसका प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा संस्थाओं तथा भूमंडलीकरण से और भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी दूसरी सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों का अभाव न सही, उनमें एक दूरी है । ये दूसरी संस्थाएं बैंक और वित्तीय क्षेत्र, यातायात और संचार, सांस्कृतिक उद्योग, जनसंचार माध्यम तथा वस्तुओं और सेवाओं के दूसरे उत्पादक और व्यापारी हैं । तमाम बातों के बावजूद अतीत में व्यापार की दशाओं में गिरावट की तरह आज कुछ देशों में स्टाक एक्सचेंज के चरमराने से उनकी शिक्षा व्यवस्थाओं पर घातक प्रभाव पड़ेंगे ।

इसके अलावा शैक्षिक सुधार पर भूमंडलीकरण के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने में अनेक कठिनाइयां हैं । इसका कारण शिक्षा के अनेक परस्पर-निर्भर घटक हैं और यह तथ्य है कि किसी व्यवस्था में छोटी से छोटी हलचल भी दीर्घकाल में भारी प्रभाव डाल सकती है । इसलिए इन प्रभावों के बारे में कोई भी बात भारी विनम्रता के साथ कही जानी चाहिए और उसकी व्याख्या कुछ शंका के साथ की जानी चाहिए ।

शिक्षा पर भूमंडलीकरण के प्रभावों को समझने के कम से कम दो ढंग है । पहला: शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा किस सीमा तक भूमंडलीकरण से निर्धारित हो रही है या, भविष्य की बात करें तो, भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हैं जो आने वाले दशकों में शिक्षा व्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं? दूसरा भूमंडलीकरण के प्रभावों से निपटने के लिए किस प्रकार के नीतिगत सुधार अपनाए जाने चाहिए ? क्या नीतियां बनाने वालों को चाहिए कि भूमंडलीकरण को ऐसा अटल सत्य और अपरिहार्य प्रवृत्ति मान लें जिनसे समाजों को तालमेल बैठाना होगा ? और क्या शैक्षिक सुधार का उद्देश्य यह है कि भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभावों को बरदाश्त की सीमाओं में रखते हुए उसके सकारात्मक सामाजिक परिणामों पर ध्यान दिया जाए और उनसे लाभ उठाया जाए ?

पहला सवाल लीजिए । उन्नत हो या पिछड़े सभी समाजों में किसी भी समय विशेष में अनेक प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं होती हैं जैसे- विद्यालयों की अच्छी या बुरी दशाएं, प्रदाय की परंपरागत या हाईटेक व्यवस्थाएं, रट्टा मारने से लेकर सक्रिय बाल केंद्रित शिक्षा तक पठन-पाठन की विभिन्न रणनीतियां आदि । भूमंडलीकरण और शिक्षा के संबंधों का जिक्र करते हुए हम बुनियादी तौर पर शिक्षा व्यवस्था के केवल उन भागों के परिवर्तन की बात करते है जिनका भूमंडलीकरण से संपर्क होता है । आम तौर पर शिक्षा संबंधी परिवर्तनों के क्रियान्वयन में भारी जड़ता होती है; शिक्षा में परिवर्तन धीरे धीरे रूप लेते हैं । पर साथ ही भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है । इसलिए यह मानना बेहतर होगा कि (अ) शिक्षा पर भूमंडलीकरण के प्रत्याशित प्रभाव तथा भूमंडलीकरण के फलस्वरूप शिक्षा में वास्तव में होने वाले परिवर्तनों के बीच भारी अंतर होंगे; (ब) एक अधिकाधिक भूमंडलीकृत समाज में शिक्षा में प्रत्याशित परिवर्तनों और प्रस्तावित

सुधारों संबंधी वक्तव्य सुधारों या परिवर्तनों के पूर्वानुमान नहीं होंगे। उनकी व्याख्या शैक्षिक नीतियों के उस ढांचे के अंग के रूप में की जानी चाहिए जिनकी भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति से कुछ सुसंगति हो।

दूसरा सवाल लीजिए । बहुत कुछ तो भूमंडलीकरण के भविष्य संबंधी मान्यताओं पर निर्भर है । क्या आज की प्रवृत्तियां शांति के साथ जारी रहेंगी ? क्या भूमंडलीकरण राजनैतिक-सामाजिक प्रतिरोध और उथलपुथल को जन्म देगा और फलस्वरूप 'घडी के पेंडुलम' को वहां पहुंचा देगा जहां जनता की गति, वित्तीय संसाधनों, भौतिक संसाधनों पर और जैसा कि कुछ देशों में देखा गया, विचारों पर अधिक नियंत्रण था ? हमारी मान्यता एक हंटिगटन की है या एक फुकुयामा की है, या फिर एक परिदृश्य की है जो व्यक्तियों की अपने भाग्य के मालिक बने रहने की क्षमता को बढ़ावा देता है ?

शैक्षिक सुधार : भविष्य के कार्यभार

सरोकार के ये पांच क्षेत्र इस प्रकार हैं : शिक्षा के लक्ष्य, व्यवस्था का ढांचा, शिक्षाकर्मी, परिणाम का मूल्यांकन और सरकार तथा दूसरे भागीदारों की भूमिका।

शैक्षिक लक्ष्य : नए जोर

भूमंडलीकरण के प्रभावी आयाम

व्यक्तियों के लिए मानकों का ह्रास : राष्ट्र, परिवार और कार्यजगत सामाजिक एकजुटता में योगदान देने वाली संस्थाएं हैं । भूमंडलीकरण के कारण उनके कमजोर पड़ने से ऐसे दुखी व्यक्ति पैदा होते है। जो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते, जो समाज में और अपने भविष्य में आस्था से वंचित हैं ।

समाजों का विघटन : भूमंडलीकरण के कुछ तत्वों ने कुछ समाजों को अपने विकास की प्रक्रिया तेज करने में समर्थ बनाया है । फिर भी भूमंडलीकृत जगत एक ऐसा ही जगत रहता है जो कुल मिलाकर बुरी तरह असमानता से ग्रस्त है । भूमंडलीकरण बहिस्राव, आर्थिक और सामाजिक भेदों के विकास, विभिन्न पहचानों वाले समूहों के बीच टकराव में तीखापन, समाजों में विघटन तथा सार्वभौम एकजुटता संबंधी प्रतिबद्धता के ह्रास को बढ़ावा देता है। साथ ही जीवन की जो अटल सच्चाइयां इन चुनौतियों से निपटने में मदद दे सकती है, उनसे संबंधित प्रश्नों को शुद्ध आर्थिक सरोकारों के कारण धुंधला देता है जिससे वे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाते हैं।

समाजों के विकास में असमान भागीदारी : समाजों के विकास में असमान भागीदारी आर्थिक स्तर पर विशेष चिंताजनक है । आज सामाजिक एकीकरण का कार्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, पर कार्य की दुनिया एक बुनियादी और असमाप्य परिवर्तन से गुजर रही है। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि कार्य की धारणा की दो वास्तविकताएं हैं : (1) 'कार्य यानी अमल' और (2) 'कार्य यानी रोजगार' । काम का संबंध एक ओर किसी कार्य को करने से है। दूसरी ओर काम रोजगार के माध्यम से ग्रहण किया जाता है । यह एक सामाजिक और कानूनी तौर पर निरूपित कार्य है जिसे सामाजिक एकीकरण का प्रमुख तत्व माना जाता है। मौजूदा उथल-पुथल का संबंध परस्पर विरोधी प्रकृति की दो वास्तविकताओं से है : रोजगारी काम एक दुर्लभ वस्तु बन जाता है जिससे धन के उत्पादन और उपभोग में आबादी का एक अधिकाधिक बड़ा भाग बाहर छूट जाता है । इसके विपरीत अमली काम नागरिक समाज के लिए जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक विषय रूप धारण करने लगता है । आज हमें परिवर्तन से गुजरकर खुशी होती है पर हमें यह बात माननी होगी कि रोजगारी काम सामाजिक एकीकरण का एकमात्र तत्व नहीं रह जाएगा । समाजों का विकास अमली काम के दूसरे रूपों के द्वारा होगा जिनके अनेकों उद्देश्य होंगे, जैसे साहचर्य की गतिविधियां, राजनैतिक भागीदारी तथा हितों और साझे उद्देश्यों के निरूपण में निजी निवेश आदि ।

शैक्षिक लक्ष्य के प्रभावकारी आयाम

भूमंडलीकरण कोई मूलगामी क्रांति नहीं है जो शिक्षा को पूरी तरह बदल कर रख दे । कुछ प्रवृत्तियों के जोर पर इसका प्रभाव अधिक होगा। पहली बात, हमें याद रखना होगा कि शिक्षा को अपने परंपरागत बुनियादी लक्ष्यों को अनदेखा नहीं करना चाहिए । ये हैं - पढ़ना, लिखना गणित, प्रज्ञान और कौशल का विकास । संक्षेप में जीने और अपने वातावरण से संवाद करने के लिए आवश्यक हर बात, हर वह चीज जो एक व्यक्ति को अपने समाज के जीवन में भाग लेने के लिए आवश्यक हो ।

ज्ञान-केन्द्रित समाज में व्यक्तियों के लिए अधिक स्वायत्तता : हर व्यक्ति को मुक्त विकास का अवसर देना समाज का उद्देश्य होना चाहिये । निरंतर परिवर्तनशील एक समाज में, जो अल्पायु जीवन मूल्यों को जन्म देता है, व्यक्ति को अपना स्थान ढूंढना होता है । आवश्यक यह है कि वह रूढ़ प्रकार की गतिविधियों से मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, दोनों दृष्टियों से अपने को मुक्त करे और नए आचार-विचार, आविष्कार और खोज में रुचि का विकास करे । विद्यालय से छात्रों को प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करने और नये मूल्यों की व्याख्या करने की सामर्थ्य मिलनी चाहिए । इसी से उन्हें यह योग्यता प्राप्त होगी कि वे अपने वातावरण के विकास के प्रति बराबर सचेत रह सकें । अगर व्यक्ति की स्वायत्तता को बल पहुंचाने के लिए जोरदार प्रयास नहीं किए जाते हैं तो मानव की एकता ऐसे अनेक प्रभावों के कारण खतरे में पड़ेगी जो परंपरागत मानदंडों को विस्थापित कर रहे हैं ।

सामाजिक बंधन का पुनर्निर्माण : विद्यालय में और अनौपचारिक वातावरणों में व्यक्ति शिक्षा के द्वारा ही साथ रहने की इच्छा करता और उसके लाभ जानता है - यहीं वह समूहों में काम करना, वैयक्तिक योग्यताओं का विकास करना, दूसरों की बात सुनना, इर्दगिर्द की घटनाओं के बारे में जानना, राष्ट्रीय स्तर पर हो या विश्व के स्तर पर, अपने आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक वातावरण की जानकारी पाना सीखता है। शिक्षा एक ही समाज और एक ही विश्वव्यापी गांव में साथ साथ जीने की इच्छा जगाने वाली उत्प्रेरक होनी चाहिए।

समाज का और अधिक समानतापूर्ण विकास : कार्यस्थल के लिए रचनाशील, प्रतिभाशाली और सहयोग करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है । सभी सामाजिक संस्थाओं की तरह शिक्षा को भी एक अधिक समानतापूर्ण समाज के विकास में योगदान होना चाहिए ।

मिसाल के लिए व्यक्तियों को यह सीखाना होगा कि स्थिर रोजगार से बचे समय में क्या करें और किस तरह ऐसे समय का उपयोग शिक्षा, स्वयंसेवी कार्य, समुदाय या समिति के कार्यों में भागीदारी के लिए करें ।

कुल मिलाकर एक अधिकाधिक भूमंडलीकृत लोक में लक्ष्यों की धारणा में क्रमिक रूप से यह तथ्य व्यक्त होना चाहिए कि दूसरी सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर शैक्षिक संस्थाओं को भी उन लक्ष्यों को पाने का प्रयास करना चाहिए जो अकसर केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किए और उससे जोड़े जाते हैं । शिक्षा को समाज व्यवस्था का एक अभिन्न अंग जब माना जाता है तभी जाकर शिक्षा के लिए प्रस्तावित और सामाजिक लक्ष्यों के रूप में पहचाने जाने वाले लक्ष्य सार्थक होते हैं ।

ढांचे के हर घटक के कार्यों पर पुनर्विचार

व्यक्ति की स्वतंत्रता को बल पहुंचाना, सामाजिक बंधन का पुनर्निर्माण, हरेक को विकास में भाग लेने का अवसर देना - ये शिक्षा के प्रस्तावित लक्ष्य हैं । वास्तव में ऐसे नागरिकों के समाज को पुनर्जीवन देने में शिक्षा का योगदान होना चाहिए जो अपने समुदाय देश और विश्व के मूल्यों, मुद्दों और चुनौतियों में साझीदार हों ।

नई आवश्यकताएं

नागरिकों का एक समाज : स्वायत्त, उत्पादक, सहभागी और प्रतिबद्ध नागरिकों का एक समाज बनाने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों और प्रकारों के बीच कार्यभार के विभाजन में एक मूलगामी परिवर्तन है । लाजमी तौर पर बुनियादी शिक्षा, जिसकी पैरवी जोम्तिएन में की गई, सभी नीति निर्माताओं का प्रमुख सरोकार होगा, खास तौर पर उनका जो शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि इसके लिए पूरी शिक्षा का पुनर्गठन आवश्यक होगा।

भूमंडलीकरण की विशेषता तीन प्रकार के कर्ताओं का उदय है : (1) जो भूमंडलीकरण करते हैं, (2) जिनका भूमंडलीकरण होता है, और (3) जो भूमंडलीकरण में पीछे रह जाते हैं। भूमंडलीकरण करने वालों का ध्यान पूंजी, संसाधनों; ज्ञान और सूचना के नियंत्रण पर केन्द्रित होता है । जिनका भूमंडलीकरण होता है वे सूचना में कमजोर और ज्ञान में कमजोर श्रमिक और उपभोक्ता हैं । जो इसमें पीछे छूट जाते हैं उनकी सूचना और ज्ञान तक कोई पहुंच नहीं है या बहुत कम पहुंच है । उपभोक्ता के रूप में उनमें ग्रहण की क्षमता नहीं हैं और उत्पादन के लिए उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। दोनों समाजों और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह विखंडन और विभाजन अब अधिकाधिक तीखा बनता जा रहा है । हर देश में इन तीनों प्रकार के व्यक्ति और समूह मौजूद हैं ।

कार्यों के बंटवारे का पुराना पड़ चुका, परंपरागत ढंग : परंपरागत रूप से विद्यालय-पूर्व शिक्षा को छोड़ दें तो हम लगभग हर शिक्षा व्यवस्था में तीन स्तरीय ढांचा पाते हैं : (अ) तीन बुनियादी कुशलताएं और विभिन्न विषयों का कामचलाऊ आरंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्राथमिक बुनियादी शिक्षा; (ब) विभिन्न विषयों के ज्ञान को विस्तार और गहराई देने वाली माध्यमिक शिक्षा जो दूसरे दो स्तरों को जोडती है और व्यक्तियों को सफल रहने पर उच्च शिक्षा के लिए तथा दूसरों को काम के लिए तैयार करती है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण भी शामिल है; और (स) राष्ट्र के लिए कैडर (अभियंता, प्रबंधक, शोधकर्ता आदि) तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा । यह परंपरागत त्रिमूर्ति ऐसे अधिक एकजुट जगत में अपनी प्रासंगिकता खो देती है जिसे बेहतर शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता हो। हम यहां दो परस्पर विरोधी परिदृश्य बखूबी देख सकते हैं : (अ) माध्यमिक शिक्षा की क्रमिक समाप्ति या बुनियादी शिक्षा में उसका समाहार - एक दो स्तरीय ढांचा जो पुनर्जागरण के आरंभिक वर्षों में यूरोप में प्रचलित था, और (ब) बुनियादी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच कालों

का कुछ पुनर्विभाजन । यूं तो डेलर्स आयोग ने शिक्षा के जो चार स्तंभ बताए हैं (कुछ बनना, कुछ जानना, कुछ करना और साथ रहना सीखने के लिए) वे शिक्षा व्यवस्था में सभी घटकों पर लागू होते हैं, पर शिक्षा के विभिन्न स्तरों से फिर भी अलग-अलग लक्ष्य जोडे जाएंगे।

बुनियादी शिक्षा के कार्य : भूमंडलीकरण से बुनियादी शिक्षा के कार्यभार बढ़ते हैं । भूमंडलीकृत लोक के लिए ऐसा समाज चाहिए जो तीव्र सामाजिक विकास के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचने और कर्म करने में समर्थ नागरिकों से बना हो। शिक्षा के बुनियादी तत्वों (पढ़ना, लिखना, हिसाब कर सकना) के साथ-साथ सभी नगारिकों को ये कौशल भी प्राप्त करने चाहिए । इसलिए विश्वव्यापी गांव के केन्द्र में स्थित नागरिक की रचना बुनयादी शिक्षा का दायित्व है। पर ऊपर दर्ज अधिकतर उद्देश्यों की प्राप्ति का दायित्व भी शिक्षा के इसी क्षेत्र के ऊपर आता है । अगर इस स्तर को 'जिंदगी का पासपोर्ट' बनाना है तो विद्यालय के और बहुत सारे शिक्षक संसाधनों के बलबूते पर इससे बच्चों को यह अवसर मिलना चाहिए कि वे कुछ बनना, कुछ सीखना और साथ-साथ जीना सीखें।

उच्च शिक्षा के पारंपरागत कार्यभार और नए सामाजिक प्रकार्य :समाज के लिए काडर जुटाना उच्च शिक्षा का परंपरागत दायित्व है । पर इसमें संशोधन होना चाहिए ताकि भूमंडलीकरण से पैदा नई मांगों को पूरा किया जा सके । राज्य की मांगें जिसके पास अकसर ऐसे प्रबंधक नहीं होते जो परिवर्तनों का पूर्वानुमान और उनसे तालमेल कर सकें : फर्मों की मांगें जिनको ऐसे तकनीशियन, इंजीनियर और मैनेजर चाहिए जो कार्यभार संपन्न कर सकें और जो प्रवर्तन की तीव्र प्रगति से तालमेल बिठाने के लिए तत्पर हों । विश्वविद्यालय समाज की जरूरत पूरी कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि वे राजनीतिक रूढ़िवाद के गढ़ न हों जो वे आज अकसर दिखाई देते है । विश्वविद्यालय अग्रगामी होने चाहिए : उन्हें बहस के लिए मंच पेश करना चाहिए, प्रवर्तनकारी सिद्धांतों को जन्म देना और उनका मूल्यांकन करना चाहिए । राजनैतिक तटस्थता और वैज्ञानिक कठोरता के साथ राजनैथतक और सामाजिक समस्याओं का व्शिलेषण करना चाहिए ।

माध्यमिक शिक्षा और तैयारीमूलक शिक्षा की पुरानी दुविधा का समाधान : एक ओर कहीं अधिक व्यापक उद्देश्यों और एक समृद्ध कार्यसूची से संपन्न पुनर्गठित बुनियादी शिक्षा तथा दूसरी ओर संशोधित दायित्वों और नए सामाजिक प्रकार्यों से लैस उच्च शिक्षा के बीच स्थित माध्यमिक शिक्षा अब सफल होने वालों के लिए उच्च शिक्षा तैयार और असफल रहने वालों के लिए काम की दुनिया में संक्रमण की मंजिल नहीं रह जाती । आयु पर्यंत शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का हर चरण तैयारी मूलक होना चाहिए ।

अध्यापन

एक परिवर्तनशील संसार में अध्यापन कैसे करें ?

परस्पर विरोधी मांगों वाला व्यवसाय : आज दुनिया में लगभग 20 करोड अध्यापक हैं फिर भी अनेक देशों में ढांचागत समायोजन की नीतियों के बाद सीमित सार्वजनिक संसाधनों के बीच भर्तियां की जा रही हैं । इससे उन देशों को पर्याप्त योग्यता वाले उम्मीदवारों को आकर्षित करने में सफलता नहीं मिली है । अध्यापकों के काम का महत्व कम हुआ है तथा कम वेतन और काम की बुरी दशाओं के कारण अध्यापकों के मनोबल, उसकी प्रेरणा में गिरावट, उनकी अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी जा सकती है ।

आज अध्यापक भी अपने क्षेत्र में प्रतियोगिता से परिचित है। सूचना सेवाओं के तथा संचार की नई विधियों के विकास के बाद ज्ञानदाता के रूप में अध्यापक का एकाधिकार समाप्त हो चुका है। फलस्वरूप पठन-पाठन अध्यापक के पेशे का एक सुरक्षित क्षेत्र नहीं रह गया बल्कि यह दूसरे सार्वजनिक या निजीकर्ताओं के लिए धीरे धीरे खुल रहा है। पठन-पाठन के नए सिद्धांत उन शिक्षकों की एक बडी संख्या की अध्यापन की क्षमता को चुनौती दे रहे हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं और शिक्षा के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण अपनाते हैं । मल्टी मीडिया जैसे ज्ञान पाने के नए उपायों और नई मांगों के साथ मूलगामी तालमेल आवश्यक होगा । कुछ ने तो यहां तक भविष्यवाणी की है कि अध्यापन की इन नई संभावनाओं के उदय के कारण अध्यापक रहेंगे ही नहीं। इसकी संभावना नहीं पर दूसरी ओर अध्यापक की भूमिका का विकास होगा तथा नई कुशलताओं और नई आवश्यकताओं के साथ उसका भरपूर तालमेल स्थापित होगा ।

अधिक दायित्व : साथ ही राजसत्ता को कमजोर करके और स्थानीय इकाइयों के पक्ष में शक्तियों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देकर भूमंडलीकरण अप्रत्यक्ष रूप से अध्यापकों के लिए नए दायित्व पैदा कर रहा है । शिक्षा में विकेन्द्रीकरण अगर होता है उसका मतलब होता है निर्णय की शक्तियों को स्थानीय निकायों, विद्यालयों, प्रधानाध्यापकों और कक्षा-प्रबंध के सिलसिले में अध्यापकों को सौंपना । अगर अध्यापक नए प्रबंकीय दायित्व संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं तो अधिक सहभागी, विद्यालय आधारित प्रबंध के लिए प्रयास करने वाले सुधार का भविष्य दांव पर लग सकता है ।

नये कार्यभार : आखिरी बात । नई सूचना प्रौद्योगिकियों पर भारी निर्भरता के कारण भूमंडलीकरण अध्यापन की नई कुशलताओं की अतिरिक्त मांगें पैदा करता है । वास्तव में इन प्रौद्योगिकियों का तकाजा यह है कि अध्यापक-प्रशिक्षण दो तरह की कुशलताओं के साथ संपन्न हो । पहली, इन नई प्रौद्योगिकियों को समझने के लिए नये तकनीकी कार्यकलाप और उनमें प्रयुक्त संचार की प्रक्रियाओं पर केंन्द्रित ज्ञान की आवश्यकता है । दूसरे ये प्रौद्योगिकियां सूचनाओं का एक विशाल भंडार उपलब्ध करती हैं जिसका प्रसंस्करण करके ही सूचनाओं का प्रासंगिक ज्ञान में रूपांतरण संभव होता है ।

भविष्य में अध्यापक

बुनियादी की तरफ पलटी : छह करोड अध्यापकों का प्रशिक्षण - आज दुनिया में कार्यरत 6 करोड अध्यापकों की योग्यताओं का उन्नयन और अनुकूलन कैसे किया जाए, जबकि हमें पता है कि उनके सबके पास बुनियादी शिक्षा संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण नहीं है और उन्हें निरंतर आयुपर्यंत शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं हैं ? यह एक विशाल कार्यभार और अध्यापन के पेशे के लिए एक बड़ी चुनौती है ।

एक पेशेवर, एक प्रबंधक : अध्यापकों के पेशेवर बनने का मतलब यह है कि पद्धति संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों और नियमों की जगह अब स्वायत्तता ले रही है जो स्पष्ट उद्देश्यों से तथा समुदाय के हितों के विरोधी तौर-तरीकों पर प्रतिबंध लगाने वाले नीति शास्त्र से प्रेरित हैं । मुख्य लक्ष्य को पाने अर्थात छात्रों के एक अधिकाधिक विषम समूह को शिक्षा और प्रशिक्षण देने तथा उन्हें स्थायी और परस्पर-परिवर्तनीय कुशलताएं सिखाने के लिए अध्यापकों को उनके विभिन्न कार्यों में इस तरह की स्वायत्तता मिलनी चाहिये जैसे - कक्षा के प्रबंध में, अध्यापन की रणनीतियों में फर्नीचर और कार्यस्थल की व्यवस्था में, काम के लोचदार समय अपनाने में, शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण को वैयक्तिक रूप देने में, आदि । पर यह बात स्पष्ट है कि अगर दूसरे व्यवसायों की तरह इस व्यवसाय में भी कारगुजारी और जवाबदेही के मानदंड़ों के अनुसार वेतनमान तय नहीं किया जाता तो अध्यापकों में पेशेवर वृत्ति का आना कभी संभव नहीं होगा।

सूचना समाज का मध्यस्थ : अध्यापक की भूमिका एक बड़ी हद तक परंपरागत भूमिका ही रहेगी क्योंकि कम से कम बुनियादी शिक्षा के स्तर पर आवश्यक ज्ञान को पाने के लिए छात्रों को किसी न किसी रूप में अध्यापक की सहायता की आवश्यकता पडती रहेगी । भूमंड़लीकरण और नई सूचना प्रौद्योगिकियों के उदय के साथ अध्यापक एक वक्ता न रहकर उससे अधिक एक अनुशिक्षक (ट्यूटर) बन जायेगा । इन प्रौद्योगिकियों से अध्यापक के लिए नई शैक्षिक विधियों का उपयोग संभव होगा और छात्रों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। अधिगम की प्रक्रिया का मार्गदर्शन और सर्वेक्षण करना इन बुनियादी भूमिकाओं में एक है । अपनी इन मार्गदर्शक भूमिकाओं के द्वारा अध्यापक यह सुनिश्चित कर सकता है कि शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित पाठ्यचर्या अच्छी तरह और सही अर्थ में अपनाई जाए । अंतिम बात - अध्यापक नई प्रकार की सहायताएं प्रदान करेगा : वह सिखाएगा कि सूचनाओं का क्या किया जाए । संक्षेप में, वह बच्चे को इस योग्य बनाएगा कि वह सूचनाएं तलाश करें, उनकी व्याख्या करे और सूचनाओं का एक जिम्मेदार उपभोक्ता बनें ।

शैक्षिक नीतियां

शिक्षा स्पष्ट रूप से समाज के सभी सदस्यों का साझा सरोकार है । लक्ष्यों का स्वीकार, संसाधनों की लामबंदी, प्रशासन और प्रबंध संबंधी दृष्टिकोण, इस क्षेत्र के नियम-कायदे, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की व्यवस्था, इन सबके लिए सभी सामाजिक पक्षों की किसी न किसी तरह की भागीदारी आवश्यक होगी । साथ ही सभी पक्षों की ऐसी व्यापक भागीदारी शिक्षा संस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।

राज्य के एकाधिकार का ह्रास

राज्य की कार्रवाई की क्षमता का ह्रास : अधिकांश देशों में थोड़े से अपवादों को छोड़, अभी हाल तक शिक्षा की बहुत सारी जिम्मेदारियों पर राजसत्ता का एकाधिकार था । आज अधिकांश देशों में राजसत्ता की शक्ति, उसकी विश्वसनीयता, बल्कि उसकी वैधता तक का ह्रास हो रहा है । रासत्ता अब लोक नीति, खासकर शिक्षा नीति पर एकतरफा फैसला करने की हालत में नहीं है ।

शिक्षा और बाजार : अब विशेष खतरा अर्थवाद (इकानामिज्म) का है । बाजार पर भरोसा करना राज्य के कमजोर पड़ने का विकल्प हो सकता है । फिर भी लगभग सारी मानवीय गतिविधियां बाजार की गतिविधियों से अधिकाधिक नियंत्रित हो रही हैं । राजनैतिक और नैतिक मुद्दों तक को आर्थिक मुद्दों के रूप में व्यक्त किया जा रहा है । लागत, प्रतिफल, मुनाफा और दक्षता जैसे शब्द आज शिक्षा व्यवसाय की रोजमर्रा की शब्दावली में शामिल हो चुके हैं गोया विद्यालय और विश्वविद्यालय ज्ञान बेचने वाली फर्म हों । आर्थिक कारणों से ढांचागत समायोजन की नीतियां अपनाई जा रही हैं जिनके चलते शिक्षा व्यय में कटौतियां हो रही हैं । परिणाम सुज्ञात और निराशाजनक है : विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के बीच अधिकाधिक विखंडन, उम्दा शिक्षा की सुलभता में कमी, जो पैसा देने में समर्थ हैं उन्हीं तक अच्छी शिक्षा का

सीमित होना, और सामान्यत: शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आज सर्वत्र देखी जा सकती है ।

भागीदारी का स्वरूप : भागीदारी का आयोजन

सभी पक्षों की भागीदारी से ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । राज्य और नागरिक समाज की संस्थाओं के सोपानी संबंधों को यही भागीदारी विस्थापित करती है । आदान-प्रदान और सहयोग का विकास इस मान्यता के आधार पर हो रहा है कि विश्वास और भागीदारी दूसरों के अधिक समान हो, इसके जोखिम से बचें इसके लिए यह आदान-प्रदान की नई पद्धतियों पर आधारित होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर उन नियमों और सुरक्षा उपायों पर आधारित होनी चाहिये जो भागीदारों के बीच एक माकूल संतुलन की कुछ गारंटी देते हैं ।

शिक्षा के नए पक्षधर

गैर-सरकारी संगठन : शिक्षा को बल पहुंचाने में इनकी भूमिका अहम हो चुकी है । उन्हें कभी-कभार (कठिन स्थितियों में) भी शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक नैतिक और स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के जिम्मेदार समझा जाता है । पर उनकी कार्यवाहियों के हाल के मूल्यांकन अनेक सवाल उठाते हैं जिनका संबंध (अ) लोक प्रशासन की अपेक्षा गैर-सरकारी संगठनों के काम की लागत प्रभाविता, (ब) उनके काम के पैमाने के जारी रहने की संभावना और उनकी क्षमता, और (स) उनके काम के बारे में आंकड़ों की विश्वसनीयता के स्तर से है । इन अध्ययनों का समापन उनके काम काज के बारे में भारी शंका तथा पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सावधानी भरी और सक्रिय दोनों प्रकार की नीतियों की आवश्यकता के साथ होता है ।

समुदाय : दुनिया जितनी एकजुट हो रही है, नीतियां और कार्यवाहियां उतनी ही स्थानीय हैं। *सोच जगत की काम गांव का* एक सुविख्यात नारा है जो आम तौर पर सामाजिक क्षेत्र और खास तौर पर शिक्षा में समुदायों अर्थात परिवारों, अभिभावकों, स्थानीय संगठित इकाइयों की बढ़ती भूमिका अपने आप स्पष्ट कर देता है। सामुदायिक भागीदारी अतिरिक्त संसाधनों की लामबंदी और नई धारणाओं व विचारों का विकास संभव बनाती है : (अ) यह हर समुदाय को आबादी की जरूरतों और हकीकतों के मुताबिक अधिक प्रासंगिक और प्रभावी शैक्षिक माडलों के विकास और उत्पादन में, (ब) स्थानीय सांस्कृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक स्मृतियों, सामाजिक आचार-व्यवहार के योगदान को जीवंत बनाने में, (स) वंचित समूहों, हाशिये पर पड़े लोगों, बाहर कर दिए गए लोगों की जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी करने में, (द) शिक्षा की सुलभता बढ़ाने और विद्यालय की दशा सुधारने में सहायता देती है ।

निजी क्षेत्र : हम चाहें या न चाहें, शिक्षा व्यवस्था (नीतियों के निरूपण, प्रबंध, मूल्यांकन) पर बाजार की जरूरतों, जैसे मुक्तिकरण, दक्षता, मुनाफा का आधिकाधिक दबाव बढ़ रहा है । इसके कारण बजट संबंधी बाधाएं शिक्षा के लिए वित्त के स्रोतों में विविधता ला रही है और निजी क्षेत्र से अधिक वित्तीय योगदान की मांग की जा रही है । विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि भूमंडलीकरण के कारण हम शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रावधान में एक अधिकाधिक महत्वपूर्ण भाग पर बहुराष्ट्रीय फर्मों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित होते देख रहे हैं ।

बेहतर शिक्षा के लिए भागीदारी : हमने अभी-अभी जिन भागीदारों का जिक्र किया है उन सबके प्रभाव या शक्तियां बराबर नहीं है । शिक्षा तक में निजी कंपनियों का महत्व अधिकाधिक बढ़ रहा है । अपनी खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए कंपनियों ने सफल प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की हैं; ये उनके अपने उद्देश्यों से प्रेरित हैं और अकसर एक से अधिक देशों को समेटती हैं । राष्ट्रीय और प्रबंध वाली शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थाओं की 'कार्य सूची' का तालमेल कैसे बैठाया जाए ? यहां राज्य की भूमिका नाजुक हो सकती है : उसे दक्षतापूर्ण भागीदारियों के विकास में योगदान देना; भागीदारी को बढ़ावा देना : पक्षों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना; कामों के विभाजन में, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, आदि के लिए उद्यत होना पड़ सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि एक भूमंडलीकृत लोक की भारी मांगों के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों के संरक्षण और विकास का तालमेल बैठाते हुए क्या राज्य आज इस हाल में होगा कि नागरिक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में व्यक्तिक हितों का स्वागत करते हुए सामान्य हितों को प्राथमिक्ता देने में अपनी क्षमता को फिर से स्थापित कर सकें और उसे बल पहुंचा सके ?

समाहार

इसमें शक नहीं कि शिक्षा ही भूमंडलीकरण से उत्पन्न समस्याओं के उत्तर देगी । सामाजिक पुनरेकीकरण के तत्व के रूप में शिक्षा को एक नया और विविधता से संपन्न रूप ग्रहण करना होगा पर यह खास तौर पर भविष्य में, वह प्रमुख तत्व बनी रहेगी जो व्यक्तियों को अपने भाग्य के नियंत्रण में समर्थ बनाएगी । निश्चित ही इन सबका दारोमदार शिक्षा नीतियों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर होगा । इसलिए आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति-निर्माताओं को इसके लिए प्रेरित करने की जरूरत है कि वे शिक्षा के लिए संसाधन जुटाएं ताकि शिक्षा अभीष्टतम दशाओं में अपने उद्देश्य पूरे कर सके और भूमंडलीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनें ।◆